



अधिकतम : 19°C

न्यूनतम : 09°C

खबरें छुपाता नहीं, छापता है

शाह टाइम्स

देहरादून, बुधवार 11 फरवरी 2026 देहरादून संस्करण: वर्ष 25 अंक 185 पृष्ठ 12 मूल्य रुपये 5.00

shahtimes2015@gmail.com

फाल्गुन कृष्ण पक्ष 8 विक्रमी संवत् 2082

22 श्रावण 1447 हिजरी

नई दिल्ली, मुंबईकरनगर, देहरादून, हनुमान, मुद्रावाहन, बोरो, मेरठ व लखनऊ से प्रकाशित



विदेशी निर्भरता से किसान बर्बाद, भाजपा किसान विरोधी : अखिलेश

पेज 2



पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच बहिष्कार का फैसला लिया वापस

जेल टाइम्स



मूलभूत विज्ञान की सबसे बड़ी भूमिका

सम्पादकीय



शबाणा महमूद होगी ब्रिटेन की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री !

पेज 12

संक्षिप्त समाचार

अब एआई-जनित सामग्री की देनी होगी स्पष्ट जानकारी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के लिए आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि वे प्लेटफॉर्म एआई-जनित सामग्री पर स्पष्ट रूप से लेबल (बाउंडरी) लगाएं। ऐसी सामग्री में पहचान के लिए संकेत होना चाहिए। सरकार ने कहा कि एक बार एआई लेबल लगाया जाए तो उसे हटाना या बदलना नहीं जा सकता। सरकार ने कहा कि अब सचन निर्मित या कृत्रिम रूप से बनाई गई जानकारी को स्पष्ट रूप से पहचान योग्य लेबल के साथ दिखाना अनिवार्य होगा। इसमें आइडियो, वीडियो, फोटो या ग्राफिक सहित किसी भी डिजिटल सामग्री को शामिल किया गया है, जिसे कंप्यूटर या किसी संसाधन से बनाया गया, संशोधित किया गया या बदला गया हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी फेक ऐसी सामग्री का गलत इस्तेमाल न करे। अगर कोई यूजर गैरकानूनी, अवैध, धोखाधड़ी या बर्बादी के चीन शोषण से जुड़ी सामग्री बनाए या साझा करे, तो प्लेटफॉर्म उसे रोकने के लिए स्वतंत्रता रखेगा।

दिल्ली में एक्यूआई 267 के साथ खराब श्रेणी में पहुंचा

राजधानी दिल्ली में लोकसभा के वजू 29 प्रत्यासी प्रत्यासी (एक्यूआई) 267 के साथ 'खराब' श्रेणी में पहुंच गया। राजधानी के कई हिस्सों में मंगलवार को सुबह धुंध की एक परत दिखाई दे रही थी, जबकि आसमान बिहार, बंगाल और मराठा जैसे इलाकों में एक्यूआई 'बहुत खराब' बताया गया, जिससे सड़क की लेकर्स नई दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय प्रशासन नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के डेटा के मुताबिक मंगलवार सुबह एक्यूआई सोमवार को 206 के साथ काफी ज्यादा था। सुबह करीब सात बजे, दिल्ली का औसत एक्यूआई 267 था। सबसे ज्यादा प्रभावित जगहों में, आनंद विहार में एक्यूआई 317 दर्ज किया गया, जबकि बंगाल में 333 रिपोर्ट किया गया और यह राजधानी के सबसे बड़े प्रभावित इलाके हैं।

मणिपुर के उखरल में पांच दिन के लिए इंटरनेट बंद

इरुवाल। मणिपुर में नई सरकार बनने के एक हफ्ते के भीतर ही हिंसा प्रारंभ हुई। उग्रवादियों ने उखरल जिले के तितात सड़खोला गांव में 25 घर और चार सरकारी क्वार्टरों में आग लगा दी। हिंसा के बाद पूरे जिले में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। 10 फरवरी को सुबह 11:30 बजे से आगे पांच दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं हैं। ताम्रबुल और कुकी जनजातियों के बीच हिंसक झड़प के बाद इलाके में निवासियों को सुरक्षा के लिए तितात सड़खोला में हटाने का आदेश जारी किया गया। पुलिस ने बताया कि हिंसा के दौरान प्रहसन से गोलीयां भी चलाई गईं।

हिमंता थूटिंग वीडियो विवाद में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार

शाह टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के विवादित वीडियो को लेकर सीपीआई-एम और सीपीआई के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकृत करने पर सहमत होता है। वीडियो में मुख्यमंत्री मुस्लिम लोगों की ओर अपमानजनक वृत्तियां दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के आधार पर वामपंथी नेताओं ने मुख्यमंत्री को खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सीनियर वकील निजाम पाशा ने मंगलवार को यह मामला कोर्ट जास्टिस सूर्यकांत के सामने पेश किया। उन्होंने



कहा कि असम के मौजूदा मुख्यमंत्री को भाषण और हाल में सामने आए वीडियो को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है। निजाम पाशा ने यह भी बताया कि इस मामले में संबंधित अधिकारियों को शिकायतें दी गई हैं, लेकिन अब तक किसी भी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के विवादित वीडियो को लेकर सीपीआई-एम व सीपीआई के नेताओं ने याचिका की दायर

जास्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तारीख तय करेगा। परराज्यल, 8 जनवरी को कोर्ट में पेश किया कि असम की सीपीआई एक्स हैटल से एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा सुसलमानों को गोली मारते दिख रहे हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता ने लिखा, यही है असली बीजेपी, सामूहिक हत्याएं

कांग्रेस प्रवक्ता ने लिखा कि यही है असली बीजेपी: सामूहिक हत्याएं। यह जहर, नफरत और हिंसा आप पर है, मिस्टर मोदी। उन्होंने पूछा कि क्या अलार्म और अलमस संध्या से होते हैं? वीडियो वायरल होने के बाद संसद के प्रभारी कांग्रेस महासचिव के.टी. जेगुगुपाल ने इस मुद्दे पर बीजेपी की अलमसना की।

जेगुगुपाल ने एक्स पर कहा कि एक आधिकारिक बीजेपी हैटल ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें अपसंस्कृतों की टारगेटेड, प्लानेट-ब्रेक हत्या दिखाई गई है। उन्होंने कहा कि यह नरसंहार का आह्वान

यह जहर, नफरत और हिंसा आप पर है, मिस्टर मोदी

करने के अलावा और कुछ नहीं है। एक ऐसा सचना जिसे यह फासोवावा शानन रसकों से जाले हुए है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने 27 जनवरी को कहा था कि राज्य में स्पेशल इंटेलिजेंस रिजून (एसआईआर) में 4 से 5 लाख रिजून मरतवालों को नाम मरतवा सूची से हटाए जाएंगे। उन्होंने कहा था कि हिमंता बिस्वा सरमा और भाजपा सीएम तीर पर रिजून समुदाय को खिलाफ हैं। उन्होंने लोगों से रिजून समुदाय को परेशान करने की अपील

की। उनका कहना था कि जब तक उन्हें परेशानी नहीं होगी, वे असम नहीं छोड़ेंगे। रिजून बांला भावी सुसलमानों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक अपमानजनक शब्द है। असम सीएम के मुताबिक वे सच रिजूनियों के संसाधनों, निरक्षरता और जनम पर कब्जा कर रहे हैं। रिजूनिका रिजून के रिजून में एक क्रांति के बाद प्रकाश से सरमा ने कहा जो चोरी का मतलब यह है कि हम कुछ रिजून को चुनने की कोशिश कर रहे हैं। आदर्श रूप से उन्हें असम में बोट डालने की इजाजत नहीं होगी चाहिए, रॉलफ बांग्लादेश में बोट देना चाहिए।

लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश

शाह टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पर से हटाने के लिए उनके खिलाफ कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों ने मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा सचिवालय को सौंपा है।

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार नोटिस लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेक के सुरेश ने लोकसभा महासचिव उपलक्ष कुमार सिंह को उनके कार्यालय में जाकर दिया है। नोटिस के प्रस्ताव पर कुल 118 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। लोकसभा में कांग्रेस के सांसदों की संख्या 99 है। विपक्ष के लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध दायर इस अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में लागू एक आरोपों की जांच होगी। कांग्रेस के अनुसार जांच प्रक्रिया के बाद इस नोटिस पर आगे की कार्रवाई को लेकर सचिवालय विचार करेगा। सूत्रों के



नोटिस के प्रस्ताव पर कुल 118 सदस्यों के हस्ताक्षर, लोकसभा में कांग्रेस के सांसदों की संख्या 99

अनुसार अविश्वास प्रस्ताव का यह नोटिस श्री बिरला को पर से हटाने के लिए अनुच्छेद 94(3) के तहत दिया गया है। उन पर आरोप लगाया गया है कि वह सदन को

अविश्वास प्रस्ताव में हुई बड़ी चूक

2026 की जगह लिखा 2025 नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की विपक्ष की कोशिश उस समय अटक गई, जब प्रस्ताव के नोटिस में तकनीकी खामियां पाई गईं। नोटिस में वर्ष 2026 की जगह बार-बार 2025 लिखा गया था, जिसे गंभीर प्रक्रियागत चूक माना गया। इसके बाद कांग्रेस के संसोधित नोटिस के साथ प्रस्ताव दोबारा जमा करा पड़ा। प्रक्रियागत त्रुटियों के अनुसार, जिसमें फी प्रस्ताव में सभी जांचकारियों का सही और तथ्यात्मक रूप से सही होना अनिवार्य होता है। साल की गलती सामने आने के बाद नोटिस को स्वीकार नहीं किया गया, जिससे विपक्ष को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। यह मामला संसदीय भी चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनकुड़ के खिलाफ लागू एक प्रस्ताव को भी तकनीकी कारणों से खारिज कर दिया गया था।

कार्यवाही पसतपूर्ण तरीके से संचालित कर रहे हैं। नोटिस में कहा गया है कि वह सला पक्ष के सदस्यों का पुराना समय सदन में बोलने का देते हैं, जबकि विपक्षी

पेंग्विन रैंडम हाउस ने कहा: अभी प्रकाशित नहीं हुई नरवणे की किताब

शाह टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली। लोकसभा में चल रहे जनरल मनोज नरवणे की किताब 'फोर स्टार्स टॉफ डेनोटिंग' से जुड़े विवाद के बीच पुस्तक के प्रकाशक पेंग्विन रैंडम हाउस इंडिया ने कहा कि उसके पास इस किताब के प्रकाशन अधिकार हैं और उसने अब तक इसे किसी भी रूप में प्रकाशित नहीं किया है।

प्रकाशक ने अपने अधिकारियों 'एक्स' अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा कि जनरल नरवणे का संस्मरण डिजिटल रूप या प्रिंट रूप में न तो जनता के सामने रिलीज किया गया है, न वेबा गया है और न ही विवरित किया गया है। पीआरएचआई ने चेतावनी दी कि किताब का प्रिंट या पीडीएफ स्वरूप साझा करना उसके कॉपीराइट का उल्लंघन होगा। प्रकाशक ने कहा कि वह बिना इजाजत के इस पुस्तक का वितरण करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेगा। बयान में कहा गया कि अपनी स्थिति साफ करने के लिए स्पेक्टोरन रिपोर्ट में रखा जा रहा है। यह विवाद

किताब पर जनरल नरवणे की पहली प्रतिक्रिया

नई दिल्ली। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज पुरंदरी नरवणे की अप्रकाशित किताब को लेकर संसद में गतिरोध जारी है। इसी बीच पूर्व सेना प्रमुख ने विवाद पर विचार लगा दिया। उन्होंने संसदीय सेशन में पेंग्विन एक्स पर किताब से संबंधित प्रकाशक पेंग्विन रैंडम हाउस इंडिया के आधिकारिक बयान को रीपोस्ट किया। इससे पहले प्रकाशन के दावा थे कि कंपनी द्वारा पुस्तक को कोई भी प्रति मुद्रित या डिजिटल रूप में प्रकाशित, वितरित, बेची या किसी अन्य तरीके से जताते के लिए उपस्थित नहीं करेगा।

पिछले हफ्ते तब शुरू हुआ, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के

मुझे लगता है जनरल नरवणे सही बोल रहे हैं : राहुल गांधी

नई दिल्ली। 'राहुल गांधी ने कहा कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब के प्रकाशन को लेकर हम की जो स्थिति सामने आई है उसमें सही बात लगती है जो जनरल नरवणे को कर रहे हैं। श्री गांधी ने संसद भवन परिसर में 'प्रकाशकों के बयान पर कहा कि पूर्व सेना प्रमुख कहते हैं कि किताब छपी है और उसे ऑनलाइन खरीदा जा सकता है जबकि पुस्तक के प्रकाशक पेंग्विन इसके प्रकाशन से इनकार कर रहा है। दुविधा की इस स्थिति में उन्हें लगा है कि उन्हें सही बात कहनी पड़ी होगी।

अभिभाषण पर धनवाद प्रस्ताव पर बहस में हिस्सा लेते हुए अपने भाषण के -शेष पृष्ठ दो पर

सम्मेल प्रकरण: एसपी अनुज चौधरी को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत

प्रकारण। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संघर्ष की सीजेएम अदालत द्वारा एसपी अनुज चौधरी समेत पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।

आदालत ने तत्कालीन तत्कालीन इंस्पेक्टर अनुज तोमर को भी राहत प्रदान की है। न्यायाधीश सतिश गोपाल का एकलपक्षी ने 9 जनवरी को पारित संघर्ष सीजेएम न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए रिशायदगर्कालों से दोनो याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले को अगली सुनवाई पांच सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि संघर्ष के सीजेएम विभागीय सुधीर ने दर्ज प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत एसपी अनुज चौधरी सहित 20 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था।

यूजीसी नियमों ने उलझाई भाजपा की हिंदू एकजुटता की राजनीति

शाह टाइम्स ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भाजपा की हिंदू एकजुटता के हिंदू महासभाओं का धर्म के आधार पर एकजुट करने की रणनीति पर काम कर रही थी।

केंद्रीय मंत्री योगी आश्रित्वरथ को बूझने की कोशिश, एक सत्र, तो सेफ रेंजों और प्रमुखमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सत्रों तो के रेंजों जैसे सत्रों के लिए पाटी जातिगत हिंसा के दौरान प्रहसन से गोलीयां भी चलाई गईं।

नए नियमों ने रणनीति को इटका दिया, उप्र की राजनीति में आई असहजता पैदा कर दी

कर रही थी। हालांकि, केंद्र सरकार के अधीन विधिविधायक अनुदान विभागीय पेशाव रोकने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष सुरक्षा प्रावधान कि



दी है। यूजीसी के नए नियमों में उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित पेशाव रोकने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष सुरक्षा प्रावधान कि

नियमों पर अंतरिम रोक लगा दी है, लेकिन राजनीतिक विरोधकों का कहना है कि तब तक नुकसान हो चुका है। नियमों को लेकर पैदा हुए असंतोष ने एक बार फिर हिंदू समाज के भीतर जातिगत विभाजन को उजागर कर दिया है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेताधिकाता के अनुसार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की चुनौती मजबूती आधाण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ और भूमिहार जैसे वर्गों पर टिकी रही है। इन्हें पार्टी का चर चोर माना जाता है।

मथुरा में एक ही परिवार के पांच लोगों की संदिग्ध मौत

शाह टाइम्स ब्यूरो

मथुरा। उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले के महाजन क्षेत्र स्थित सुयूपर गांव में मंगलवार को एक ही परिवार के पांच सदस्यों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में उनके घर से बाहर पाए जाने से सनसनी फैल गई। घातकों की पहचान साफ नहीं, उनकी पत्नी सीमा और उनके तीन बच्चों के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, सुबह काफी रेंड तक घर से कोई बाहर नहीं निकला तो मनीष के पिता सुधीर को अनसुनी की आशंका हुई। उन्होंने दीवार फांदकर घर में प्रवेश किया और कमरे का दरवाजा तोड़ा। अंदर बेड पर मां और दो बच्चों के शव पड़े थे, एक बेटी का शव कारपाई पर मिला, जबकि मनीष का शव फर्श पर पड़ा था। मरिच पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) शलोक कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला 'हत्या' के बाद आत्महत्या' का प्रतीत हो रहा है। पुलिस के अनुसार आशंका की कि मनीष ने पहले पत्नी की हत्या की, फिर सोते हुए तीनों बच्चों का गला घोट दिया और अंत में स्वयं करंट लगाकर

प्रारंभिक जांच में मामला 'हत्या' के बाद आत्महत्या' का प्रतीत हो रहा : एसएसपी

आत्महत्या का लो लो के घर खून के निशान भी मिले हैं। पुलिस को प्रहसन के उल्लेखपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। कमरे की रोबोट पर एक सुसाइड नोट लिखा मिला है, जिसमें मनीष और सीमा द्वारा अपने पार्स से जान देने की बात कही गई है और पुलिस से किसी को परेशान न करने का अनुरोध किया गया है। एक कागज पर भी कथित सुसाइड नोट मिला है। इसके अलावा मनीष के मोबाइल फोन से 48 संकेतों का एक वीडियो बायाम हुआ है, जिसमें उसने आत्मघाती करम उठाने की बात कही है। हालांकि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या से जुड़ा प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुलिस अन्य संभावित प्रत्युत्तरों जैसे आसपी रीजिया या अलगावों की भी गंभीरता से जांच कर रही है। फॉरेंसिक एक्स ने मौत के साथ एकत्र किए गए और सभी शवों को पोस्टमार्टम से लिए भेज दिया गया है।

ताकि अन्य जरूरतमंद विभागों को वह पैसा आसानी दिया जा सके।

लिले के लिए एक बड़ी घोषणा करने हुए सीडीओ ने बताया कि विकासमन्त्री ब्रज्ज के कपटस्थर और रायपुर स्थलिक के कार्यालय को 'आदर्श ग्राम' के रूप में विकसित किया जाएगा।

इन गांवों को शरीर सरकारी योजनाओं से शरत-प्रतिशत आच्छादित करने के लिए सभी विभागों को एक समन्वित कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं।वेक में सोमपड और ड. उपके शर्मा, पीडी विभाग स्थित पंवार और जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार सहित तमिषा जिला सरकी अधिकारी मौजूद रहे।

सूचना (संबंध विच्छेद)
मैंने अपने पुत्र शहाबाज व उसकी प्रती श्रीमती गुलिसाज को अपनी समस्त चर व अन्तर् सम्पत्ति से वेदवल्ह कर अपने सभी संबंध विच्छेद कर लिये हैं। भविष्य में इन दोनों के किसी भी लेन-देन व कृत्त को जिम्मेदारी नहीं व मेरे परिवार को नहीं होगा। श्रीमती पुत्र स्व. श्री जरीफ, निवासी मो. पान्थोई, ज्वालापुर, हरिद्वार।

हरिद्वार में समाचार व विज्ञापन के लिये सम्पर्क करें।

सैफ सलमाना
ब्योरो चीफ
शाह टाइम्स हरिद्वार
कार्यालय : रामगढ़, नहरीली के पीछे, ज्वालापुर, हरिद्वार
मो. : 9639554326, ई-मेल :
shahitimesh2027@gmail.com
